Date - 10 March 2022

मिशन इन्द्रधनुष

- सफल COVID-19 टीकाकरण के अलावा, ओडिशा में 5% कवरेज के साथ देश में पूर्ण टीकाकरण का उच्चतम कवरेज है।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार, 90.5% कवरेज के साथ ओडिशा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है।
- सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 0 पर समीक्षा बैठक के दौरान, जिसे 7 मार्च को राज्य भर में लॉन्च किया गया था, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, आर.के. शर्मा ने इसका जिक्र किया।
- ओडिशा के बीस जिले पूर्ण टीकाकरण में 90 प्रतिशत से ऊपर थे, जबकि शेष 10 जिले 90 प्रतिशत से नीचे थे।

पूर्ण टीकाकरण में क्या शामिल है?

- पूर्ण टीकाकरण में 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ निवारक खुराक शामिल है। इस बीमारी में तपेदिक, पोलियो, डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस, काली खांसी, दिमागी बुखार, एचआईवी, खसरा, निमोनिया, दस्त, रूबेला, जापानी बुखार और अन्य शामिल हैं।

टीकाकरण अभियान

- आईएमआई के तहत टीकाकरण अभियान तीन दौर में चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दौर में अलग-अलग टीकों की अलग-अलग खुराक दी जाएगी। पहले असंबद्ध या आंशिक रूप से टीकाकृत गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित किया जाएगा।
- टीकाकरण तीन राउंड में होगा, पहला 7 मार्च से शुरू होगा, दूसरा 4 अप्रैल से और तीसरा इस साल 2 मई से, प्रत्येक राउंड सात दिनों तक चलेगा।

मिशन इन्द्रधनुष

Yojna IAS

- मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक स्वास्थ्य देखभाल पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है।
- काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, बचपन के तपेदिक के गंभीर रूप, खसरा और निमोनिया और हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिन्जाइटिस के खिलाफ टीकाकरण के साथ-साथ चयनित राज्यों और जिलों में टीकाकरण भी किया जा रहा है। एन्सेफलाइटिस और रोटावायरस डायरिया।

सघन मिशन इन्द्रधनुष

- टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) का शुभारंभ किया। सरकार को दो साल से कम उम्र के हर बच्चे के साथ-साथ नियमित टीकाकरण से छूटी हुई सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम।
- इस विशेष अभियान का लक्ष्य 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% कवरेज तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ कुछ जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देना था।

गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0

- सभी उपलब्ध टीकों के साथ अगम्य लोगों तक पहुंचने और 2019 दिसंबर से 2020 मार्च तक निर्दिष्ट ब्लॉकों के साथ-साथ जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज में तेजी लाने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 0 दिसंबर, 2019 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य 2030 तक बच्चों की परिहार्य मृत्यु को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना भी है।

गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0

- गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 0 योजना उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिए लागू की गई थी जो कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण से चूक गए हैं।

गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0

- गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 0 हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- सुनिश्चित करें कि गैर-टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस अभियान के तहत दो साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा।

YojnaIAS

खाद्य तेल: भारत

- सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के कारण, खाद्य तेल की कीमतें पिछले दो वर्षों से नियंत्रण में हैं, भले ही कोविड की स्थिति कुछ भी हो।
- हालांकि, यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण, खाद्य तेलों सहित कई वस्तुओं की कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं।

संबंधित मामला:

- भारत का सूरजमुखी तेल का घरेलू उत्पादन मांग के एक चौथाई से भी कम है, और इसकी अधिकांश आपूर्ति यूक्रेन से होती है। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित होने से यह आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।
- सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति कम होने के कारण उपभोक्ता मूंगफली और पाम तेल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनके दाम बढ़ रहे हैं।

खाद्य तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि:

- पिछले साल छह खाद्य तेलों- मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम/पाम ऑयल की खुदरा कीमतों में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी। इसके निम्नलिखित कारण थे:
- वैश्विक कीमतों में उछाल, और कम घरेलू सोयाबीन उत्पादन। सोयाबीन भारत की सबसे बड़ी तिलहन फसल है।
- चीन द्वारा खाद्य तेल की अत्यधिक खरीद।
- कई प्रमुख तेल उत्पादक 'जैव ईंधन' का उत्पादन करने के लिए खाद्य तेल फसलों का उपयोग करते हुए आक्रामक रूप से जैव ईंधन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
- सरकारी कर और शुल्क भी भारत में खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य का एक बड़ा हिस्सा हैं।

YojnaIAS

खाद्य तेल आयात पर भारत की निर्भरता:

- भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा आयातक है।
- भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% आयात करता है, जिससे देश में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- देश मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल और रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल आयात करता है।

खाद्य तेलों के बारे में मुख्य तथ्य:

- खाद्य तेल के प्राथमिक स्रोत सोयाबीन, सफेद सरसों (रेपसीड) और सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर हैं। खाद्य तेल के द्वितीयक स्रोत 'ताड़ का तेल', नारियल, चावल की भूसी, कपास के बीज और वृक्ष-जनित तिलहन हैं।

भारत में तिलहन उत्पादन में प्रमुख चुनौतियां:

- तिलहन का उत्पादन मुख्य रूप से 'वर्षा सिंचित' क्षेत्रों (क्षेत्र का लगभग 70%) में किया जाता है।
- बीज (मूंगफली और सोयाबीन) की उच्च लागत,
- सीमित संसाधनों के साथ छोटी जोत,
- कम बीज प्रतिस्थापन दर और कम उत्पादकता।

पाल-दाधव नरसंहार: गुजरात

- गुजरात में 7 मार्च को हुए 'पाल-दाधव हत्याकांड' ने 100 साल पूरे कर लिए। गुजरात सरकार ने इसे "जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार" बताया है।

पाल-दाधव नरसंहार के बारे में:

- यह नरसंहार 7 मार्च, 1922 को साबरकांठा जिले के पाल, चितरिया और दधवाव गाँवों में हुआ था, उस समय ये गाँव 'इदर रियासत' (वर्तमान गुजरात) का हिस्सा थे।
- मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 'एकी आंदोलन' के तहत पाल, दधव और चितरिया के ग्रामीण 'वारिस नदी' के तट पर एकत्रित हुए।
- यह आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू-राजस्व कर (लगान) के विरोध में किया जा रहा था।
- ब्रिटिश अर्धसैनिक बल लंबे समय से 'तेजावत' की तलाश में थे। इस भीड़ की जानकारी मिलते ही ये बल तुरंत मौके पर पहुंच गए।
- तेजावत के नेतृत्व में करीब 2000 भीलों ने धनुष-बाण उठाकर लगान न देने के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस पर ब्रिटिश कमांडर एचजी सटन ने ग्रामीणों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और इस अंधाधुंध गोलीबारी में करीब 1,000 आदिवासी (भील) मारे गए।
- हालांकि मोतीलाल तेजावत गोलीबारी में बाल-बाल बच गए, और बाद में उन्होंने लौटकर इस जगह का नाम 'वीरभूमि' रखा।

विरासत:

- इस नरसंहार की शताब्दी पर गुजरात सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस घटना को "1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर" बताया गया है।

Yojna IAS

स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना (SSSY) और इसके घटकों को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय रुपये 3,274.87 करोड़ निर्धारित किया गया है|

पृष्ठभूमि:

- पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में 'पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' शुरू की गई थी।
- स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की एक नियमित योजना वर्ष 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी।
- 1980 से 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' नामक एक उदार योजना लागू की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का नाम बदलकर 'स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना' कर दिया गया है।
- पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया गया है और वर्ष 2016 से महंगाई राहत भी प्रदान की जा रही है।

योजना के बारे में:

- यह योजना स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के रूप में मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
- पात्र आश्रितों यानी पति या पत्नी और अविवाहित और बेरोजगार बेटियों और आश्रित माता-पिता को उनकी मृत्यु पर निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।

Swadeep Kumar

Yojna IAS